THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) and (b). Recruitment in the industrial establishments of Telecom. Factories and Telcom. Organisation is normally made in the unskilled grade and the posts in semi-skilled, skilled and highly skilled grades are filled up by promotion, subject to the workers concerned passing the prescribed trade test. Only a small percentage of workers have reached the maximum of the scale of pay in their recuritment cadre and they could not be promoted to the next grade mostly because of not passing the prescribed trade test or being unfit.

50 new Coal Mining Projects in jeopardy

3291. PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than fifty new coal mining projects are in jeopardy because of the non-fulfilment of the Planning Commission's commitment to meet the financial constraints;

(b) if so, details thereof stating the names of the States in which these new coal mining projects were proposed to be taken; and

(c) reasons for the non-fulfilment of the Planning Commission commitment and its likely impact on the targeted coal production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRA M MAHAJAN) : (a) to (c). The question of allocation of additional funds for development of coal mines is under the consideration of Government . The impact of this on the different projects can be determined only after a final decision has been taken by Government.

ऊर्जा के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

3292. **श्री सज्जन कुमार :**
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत को ऊर्जा के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के विकास के लिए ऋण की इस राशि को किस तरह खर्च किया जाएगा और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) . कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना के दूसरे सोपान (3×500 मेगावाट तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण लाइनों) के लिए लगभग 320 करोड़ रुपयों (400 मिलियन यू० एस० डालर) के एक ऋण के लिए विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण) के साथ अप्रैल-मई 1981 में बात चीत आरम्भ की गई थी तथा विश्व बैंक द्वारा इसे जुलाई, 1981 में स्वीकृति दी गई थी। इस ऋण से सम्बन्धित करारों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है ।

2100 मेगावाट की चरम क्षमता वाला कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में किया जा रहा है ।

यह उल्लेखनीय है कि अभी तक विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता ली गई है और इनके सम्बन्ध में करार हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन करारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है ।